



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931

No. 268]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : ताईवान एवं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल की या वहां से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल पालिस्टर फिल्म के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

पृष्ठभूमि

फा. सं.15/17/2008-डीजीएडी.— यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25-7-2003 की अधिसूचना सं. 14/53/2002-डीजीएडी के तहत अनंतिम शुल्क लगाने की संस्तुति की और भारत सरकार द्वारा दिनांक 26-8-2003 की सी.शु. अधिसूचना सं. 133/2003 के तहत ऐसा अनंतिम शुल्क लागू किया गया था । प्राधिकारी ने यूएई तथा चीनी ताइपेई (ताईवान) (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की या वहां से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल पालिस्टर फिल्म (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 30-7-2004 की अधिसूचना सं. 14/53/2002-डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे और भारत सरकार ने दिनांक 29.9.2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 101/2004 द्वारा ऐसा निश्चयात्मक शुल्क लागू किया था ।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार इस आधार पर संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे आगे और 5 वर्ष की अवधि तक जारी रखने का अनुरोध करते हुए मै. गरबारे पालिस्टर लि., मुंबई से एक पुष्टिकृत आवेदन प्राप्त हुआ कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयात जारी रहा है । यह

भी दावा किया गया था कि उपाय की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संबद्ध देशों के खिलाफ संभावना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किये जाने से पाटन, क्षति या दोनों की पुनरावृत्ति होने या उसके जारी रहने की संभावना है, पाटनरोधी शुल्क (निर्णायक समीक्षा) जांच शुरू करते हुए 14 अगस्त, 2008 को एक सार्वजनिक सूचना सं. 15/17/2008-डीजीएडी जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

क. प्रक्रिया

3. इन कार्यवाहियों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i) समीक्षा शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने संगत सूचना मांगने के लिए नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजी।
- ii) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार इस अनुरोध के साथ जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें।
- iii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थी।
- iv) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां व्यापक प्रचालन हेतु फिक्की, सीआईआई तथा एसोचेम को भी भेजी गई थी।
- v) संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक तथा उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्राधिकारी को नहीं दिया है।
- vi) किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- vii) घरेलू उद्योग होने के कारण मै. गरवारे पोलिस्टर लि. ने सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए। प्राधिकारी ने हुई क्षति की जांच करने के लिए उत्पादन की इष्टतम लागत, भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया।

- viii) हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता को मंजूरी प्रदान की और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के समक्ष उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पार्टियों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- ix) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आईबीआईएस के आंकड़ों के अलावा, जांच अवधि एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए आयातों के सौदेवार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से मांगे गए थे।
- x) *** चिन्ह इस विवरण में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने उसे नियमानुसार गोपनीय ही माना है।
- xi) * हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए प्राधिकारी ने दिनांक 17.7.2009 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें हितबद्ध पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है;
- xii) यह जांच 01.04.2007 से 31.3.2008 तक की जांच अवधि के लिए की गई थी। तथापि, क्षति विश्लेषण में 2004 - 05, 2005 - 06, 2006 - 07 तथा जांच अवधि शामिल है।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु:

4. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद ताईवान एवं यूई के मूल की या वहां से निर्यातित "विशिष्टता युक्त पालिस्टर फिल्म अर्थात् सन/डस्ट कंट्रोल पालिस्टर फिल्म" है जिसे व्यापारिक एवं बाजारी भाषा में सन कंट्रोल फिल्म, सन फिल्म, सोलर फिल्म, सोलर कंट्रोल फिल्म, सोलर विंडो फिल्म, विंडो फिल्म जैसे अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। इस उत्पाद का व्यापक रूप से उपयोग ताप अस्वीकरण/चमक न्यूनीकरण, यू/वी अल्ट्रावाइलेट अस्वीकरण के लिए किया जाता है और इसका सुरक्षित उपयोग आटोमोबाइलों एवं भवनों आदि की खिड़कियों पर लगे शीशों पर किया जाता है। सन/डस्ट कंट्रोल पालिस्टर फिल्म का उपयोग कांच की खिड़कियों के अंदरूनी भाग पर किया जाता है। इसका मुख्य कार्य सौर ताप, चमक, पराबैंगनी प्रकाश एवं चमक को कम करना है, जो सामान्यतः खिड़कियों के जरिए प्रवेश करती है। सन/डस्ट कंट्रोल पालिस्टर फिल्म सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत टैरिफ शीर्ष 39 20 69 तथा भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के शीर्ष 39.20.69.04 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथापरिभाषित उत्पाद के समान ही रहता है। इसके अलावा, इसके बाद की अवधि के दौरान उत्पाद में किसी पर्याप्त विकास या परिवर्तन का कोई दावा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित

वस्तु संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तुएं हैं। विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु का खंडन करते हुए किसी निर्यातक/उत्पादक या किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई अनुरोध नहीं किया है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग तथा आधार:

5. मूल जांच में मै. गरवारे पालिस्टर लि., मुंबई ने प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर की थी। निर्णायक समीक्षा आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में मै. गरवारे पालिस्टर लि., मुंबई द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक होने के नाते याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है। जांच से ऐसे किसी तथ्य का पता नहीं चला है जो याचिकाकर्ता के द्वारा किए गए दावे और पुष्टिकरण के विपरीत हो। नियमों एवं रिकार्ड में उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मै. गरवारे पालिस्टर लि., मुंबई नियमों के अर्थ के भीतर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग है।

घ. पाटन मार्जिन

घ.1 निर्धारण की कार्य प्रणाली

6. ताईवान तथा यूएई के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

घ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

घ.2.1 समान मूल्य

7. संबद्ध देशों के किसी निर्यातक/उत्पादक ने जांच में सहयोग नहीं किया है ताकि उनके देशों में संबद्ध वस्तु के समान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण किया जा सके और प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :

- (i) याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्होंने उस कीमत के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है जिस कीमत पर निर्यातकों द्वारा अपने घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की बिक्री की जा रही थी, तथापि जिस कीमत पर भारत को वस्तु का निर्यात किया गया है वह संबद्ध वस्तु के उत्पादन से संबद्ध लागत से काफी कम है।
- (ii) याचिकाकर्ता ने बताया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात ताईवान को किया है। इस उत्पाद की ताईवान में सीधे खपत नहीं की जाती है। आयातकों द्वारा इस

उत्पाद की पुनः बिक्री की जाती है। याचिकाकर्ता द्वारा निर्यातित वस्तु की जिस कीमत पर ताईवान के बाजार में आयातक द्वारा एतद्वारा पुनः बिक्री की जाती है, वह उस कीमत से काफी अधिक होगी जिस कीमत पर याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। याचिकाकर्ता द्वारा ताईवान की संबद्ध वस्तु का जिस कीमत पर निर्यात किया गया है वह ताईवान के बाजार में बेचे जा रहे विचाराधीन उत्पाद की कीमत से कम रही है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा ताईवान में उत्पाद की बिक्री जिस कीमत पर की जा रही है वह ताईवान में सामान्य मूल्य का पारंपरिक अनुमान है।

- (iii) कि विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त उत्पादन प्रौद्योगिकी या विनिर्माण प्रक्रिया अंतर्ग्रस्त नहीं होती है। इससे यह भी प्रतीत नहीं होता है कि प्रचालनों की मात्रा से उत्पादन लागत में पर्याप्त अंतर आ सकता है। इन तथ्यों के मद्देनजर प्राधिकारी ने परिकलित मूल्य की पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन किया है और उन्होंने इस मामले में किसी निर्यातक/उत्पादक का सहयोग न होने पर भी अत्यंत पारंपरिक तरीका अपनाया है।
- (iv) कि पालिस्टर फिल्म संबद्ध वस्तु के उत्पादन की प्रमुख कच्ची सामग्री है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तु के निर्माण में अनेक रसायनों/संयोजकों का उपयोग किया जाता है।
- (v) तुलना के आधार पर 2 विकल्प के बारे में निर्धारित सामान्य मूल्य से यह पता चलता है कि उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य अधिक पारंपरिक एवं उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त स्पष्ट की गई परिस्थितियों में सामान्य मूल्य का आकलन नियम 6(8) के अनुसार बिक्री/सामान्य/प्रशासनिक लागत एवं लाभ हेतु उचित अभिवृद्धि के साथ उत्पादन लागत के बारे में किया गया है।

ताईवान

8. किसी निर्यातक/उत्पादक से किसी सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने सर्वोत्तम सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। ताईवान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन प्रमुख कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क, समुद्री भाड़े एवं समुद्री बीमा की राशि द्वारा विधिवत समायोजित अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर किया गया है। अन्य कच्ची सामग्री, परिवर्तन लागत, सामान्य एवं प्रशासनिक तथा बिक्री व्यय को 5% लाभ मार्जिन के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के अनुसार स्वीकार किया गया है। संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य 40.75 रूपए = 1.00 अम.डॉ. की विनिमय दर से *** रूपए (***) अम.डॉ. प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

यू.ई

9. किसी निर्यातक/उत्पादक से किसी सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने सर्वोत्तम सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। यू.ई के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन प्रमुख कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क, समुद्री भाड़े एवं समुद्री बीमा की राशि द्वारा विधिवत समायोजित अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर किया गया है। अन्य कच्ची सामग्री, परिवर्तन लागत, सामान्य एवं प्रशासनिक तथा बिक्री व्यय को 5% लाभ मार्जिन (ब्याज को छोड़कर) के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के अनुसार स्वीकार किया गया है। संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य 40.75 रुपए = 1.00 अम.डॉ. की विनिमय दर से *** रुपए (***) प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

घ.2.2 निर्यात कीमत

10. याचिकाकर्ता ने गौण एजेंसी मै. इनफार्मेट, मुंबई द्वारा प्रदत्त वास्तविक आयात के आंकड़ों के आधार पर आयातों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए सौदेवार आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से मांगे गए थे और वे प्राप्त हो गए थे। आंकड़ों से यह देखा गया है कि एक खास वर्गीकरण के अंतर्गत अलग-अलग उत्पादों का आयात किया गया है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आंकड़ों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से केवल एक सौदा हुआ है जिसमें आयात की मामूली मात्रा प्रदर्शित की गई है। निर्यातकों से वास्तविक निर्यात कीमत के अभाव में प्राधिकारी ने शामिल देशों से निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु इस सूचना को अपनाया है।

11. प्राधिकारी ने संबद्ध निर्यातकों द्वारा पूर्ण असहयोग को ध्यान में रखते हुए समुद्री भाड़े तथा बीमा के लिए समायोजनों के बाद भारित औसत निर्यात कीमत निकाली है।

ताइवान

12. ताइवान से आयातों की सीआईएफ निर्यात कीमत *** रुपए/किग्रा. अर्थात् *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. निकाली गई है तथा समुद्री भाड़े एवं बीमा के लिए समायोजनों के बाद निवल निर्यात कीमत *** रुपए (***) प्रति किग्रा. निर्धारित की गई है।

संयुक्त अरब अमीरात

13. यू.ई से आयातों की सीआईएफ निर्यात कीमत *** रुपए/किग्रा. अर्थात् *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. निकाली गई है तथा समुद्री भाड़े एवं बीमा के लिए समायोजनों के बाद निवल निर्यात कीमत *** रुपए (***) प्रति किग्रा. निर्धारित की गई है।

घ.3 पाटन मार्जिन

14. निर्यात के देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत की तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार उपबंध है :-

"पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेंगे। यह तुलना व्यापार के समान स्तर, सामान्यतः कारखाना स्तर पर और लगभग उसी समय के आसपास की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। बिक्री की शर्तों एवं निबंधनों, कराधान में परिवर्तनों सहित कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अंतरों, व्यापार के स्तर, मात्रा, भौतिक विशेषताओं तथा कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित अन्य अंतरों के संबंध में प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर विधिवत छूट प्रदान की जाएगी।"

15. उपरोक्त नियम के अनुसार प्राधिकारी ने भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना पाटन मार्जिन की गणना हेतु भारित औसत निवल निर्यात कीमत के साथ की है।

16. सहयोग के अभाव को ध्यान में रखते हुए दोनों संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का परिकलन सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है और पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारित औसत सामान्य मूल्य अपनाया गया है। भारित औसत निवल निर्यात कीमत का आकलन भी पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुमत्य समायोजनों के अनुसार डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना नियमावली के अनुबंध-1 के अर्थ के भीतर उचित है।

17. तदनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निकाला गया है :-

देश-वार निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डॉ./प्रति कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अम.डॉ./प्रति कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अम.डॉ./प्रति कि.ग्रा.,	पाटन मार्जिन रेंज (%)
ताइवान सभी निर्यातक	***	***	***	60-70
यूएई सभी निर्यातक	***	***	***	485-495

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक था। वर्तमान जांच से भी संबद्ध देशों से पर्याप्त पाटन मार्जिन का पता चलता है।

ड. क्षति निर्धारण की कार्यप्रणाली तथा कारणत्मक संबंध की जांच

ड.1 क्षति एवं कारणत्मक संबंध

ड.1.1 याचिकाकर्ता के विचार

19. याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :-

- (i) घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार होने के बाद भी निवेश पर आय अभी भी अपर्याप्त है ।
- (ii) संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का प्रवेश घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम पाटित कीमतों पर होगा ।
- (iii) कि संबद्ध देशों के पास भारत को निर्यात हेतु भारी मात्रा में मुक्त रूप से निपटान योग्य/अप्रयुक्त/बेशी क्षमताएं हैं और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है ।
- (iv) ऐसी किसी स्थिति में जिसमें, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो और जहां घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहती हो अथवा घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी शुल्क समाप्ति की स्थिति में पुनः होने की संभावना हो, वहां पाटनरोधी शुल्क आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए । वर्तमान मामले में संबद्ध देशों से उत्पाद का पाटन जारी है । पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में तेजी आएगी ।
- (v) तथापि, यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं हुई है और याचिकाकर्ता तत्पश्चात् यह दावा करता है कि शुल्क की समाप्ति से ताईवान एवं यूएई से हुए आयातों के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होगी । जहां तक क्षति का संबंध है, समस्त मापदंडों से संचयी एवं सामूहिक रूप से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और परिवर्ती प्रतिबंध के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है तथा शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है ।

ड.1.2 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

20. संबद्ध देशों के किसी निर्यातक/उत्पादक, आयातक एवं अन्य हितबद्ध पार्टी की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है । सार्वजनिक सुनवाई के समय यूएई सरकार की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- (i) यूएई से अल्प मात्रा में आयात किए गए हैं ।
- (ii) यूएई से हुए आयात समूची क्षति अवधि में कुल आयातों के मात्र 4% और जांच अवधि में कुल आयातों के 1% रहे हैं । यह ताईवान से हुए आयातों का केवल 11% है । ताईवान और यूएई के लिए कोई संचयी निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए ।
- (iii) याचिका के अगोपनीय रूपांतरण में याचिकाकर्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि यूएई से कोई आयात नहीं हुआ है ।
- (iv) क्षति की पुनरावृत्ति को सिद्ध करना तथा "सकारात्मक साक्ष्य एवं तथ्यात्मक जांच" की अपेक्षा की पूर्ति अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत की जानी अपेक्षित है ।

ड.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि निर्णायक समीक्षा के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क(5) के संगत प्रावधानों में निम्नानुसार उल्लेख है :

"इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा :

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।"

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (i) पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में निर्णायक समीक्षा करने की प्रक्रिया दी गई है । समीक्षा करने के लिए नियम 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान लागू किए गए हैं ।
- (ii) डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव । पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना

अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती ।

- (iii) क्षति की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने पाटित आयातों की मात्रा एवं घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के प्रभाव तथा कीमतों एवं लाभप्रदता पर उनके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी एवं पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की जांच की जा सके ।

23. क्षति के संचयी निर्धारण के मुद्दे की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने निम्नलिखित पर विचार किया है और यह पाया है कि :

- (i) घरेलू उत्पाद तथा संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा आपूर्त उत्पाद समान वस्तुएं हैं ।
- (ii) आयातित उत्पाद तथा घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुएं अदल-बदल कर प्रयोग की जाती हैं और इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है । विभिन्न देशों से हुए आयातों के बारे में सौदेवार सूचना से यह पता चलता है कि आयात मुख्यतः उन व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं जिन्होंने पुनः बिक्री के लिए सामग्री की खरीद की है । अतः दोनों देशों द्वारा आपूर्त वस्तुएं एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं ।
- (vi) संबद्ध देशों से आपूर्त उत्पादों का विपणन तुलनीय बिक्री माध्यमों के जरिए और एक समान वाणिज्यिक स्थितियों में एक समान अवधि के दौरान भारत में किया गया है ।
- (vii) घरेलू उत्पादक तथा संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा उपभोक्ताओं की समान श्रेणी को उत्पाद की बिक्री की जा रही है ।

24. प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस मामले में क्षति का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात आपस में और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ।

च. क्षति निर्धारण**च.1 मांग का निर्धारण**

25. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खपत/मांग की गणना करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और भारत में हुए कुल आयातों पर विचार किया है।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी.ट.	241	279	332	355
प्रवृत्ति	मी.ट.	100	116	138	147
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	2.36	0	0.444	3.198
प्रवृत्ति		100	0	19	136
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	28.48	80.63	131.86	130.86
प्रवृत्ति		100	283	463	460
कुल आयात	मी.ट.	30.84	80.63	132.30	134.16
प्रवृत्ति		100	261	429	435
मांग	मी.ट.	271.84	359.63	464.30	489.16
प्रवृत्ति		100	132	171	180
घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री	मी.ट.	1136	1189	1276	1288
प्रवृत्ति		100	105	112	113

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और वह आधार वर्ष 2004-05 से बढ़कर जांच अवधि में 80% हो गई है जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में 47% की वृद्धि हुई है। समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयात मामूली रहे हैं।

च.1.2 आयातित मात्रा तथा बाजार हिस्सा

27. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपबंध है :-

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है"

28. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग की जांच की है। प्राधिकारी ने केवल डीजीसीआईएंडएस स्रोत के आधार पर आयातों की मात्रा की जांच की है।

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
आयातों में बाजार हिस्सा					
ताईवान	मी.ट.	2.36	-	0.444	1.076
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	19	45.59
यूएई	मी.ट.	-	-	-	2.122
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
संबद्ध देश	मी.ट.	2.360	-	0.444	3.198
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	19	136
अन्य देश	मी.ट.	28.48	80.63	131.86	130.96
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	283	463	460
कुल आयात	मी.ट.	30.845	80.626	132.300	134.16
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	261	429	435
घरेलू उद्योग की बिक्री					
मी.ट.		241	279	332	355
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	138	147
कुल मांग		271.84	359.63	464.30	489.16
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	171	180
आयातों में बाजार हिस्सा					
ताईवान	%	7.65	-	0.34	0.80
यूएई	%	-	-	-	1.58
संबद्ध देश	%	7.65	-	0.34	2.38
अन्य देश	%	92.35	100	99.66	97.62
मांग में बाजार हिस्सा					
चीनी ताइपेई	%	0.87	-	0.11	0.22
यूएई	%	-	-	-	0.43
संबद्ध देश	%	0.87	-	0.11	0.65
अन्य देश	%	10.48	22.48	28.39	26.77
घरेलू उद्योग	%	99.65	77.58	71.50	72.58

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- (i) भारत में हुए कुल आयातों में संबद्ध देशों का हिस्सा आधार वर्ष 2004-05 में 7.65% से घटकर वर्ष 2005-06 में "शून्य" हो गया और तत्पश्चात वर्ष 2006-07 में बढ़कर 0.34% हो गया एवं बांध अवधि में बढ़कर 2.38% हो गया । आधार वर्ष को छोड़कर कुल आयातों में संबद्ध देशों का हिस्सा कमसेकम 1% से कम रहा है ।
- (ii) आधार वर्ष में संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में मांग में बाजार हिस्सा केवल 0.87% था जो जांच अवधि में आगे और बढ़कर 0.85% हो गया । जांच अवधि के दौरान

कुल मांग में संबद्ध देशों का हिस्सा केवल 0.65% है जो अत्यंत कम और नगण्य है। इसी समय संबद्ध देशों का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 10.48% से बढ़कर 26.77% हो गया है। वर्ष 2004-05 में घरेलू उद्योग का हिस्सा 88.65% था जो जांच अवधि में घटकर 72.58% हो गया है।

च.1.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

30. किसी समीक्षा जांच में इस बात की जांच अपेक्षित होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है अथवा क्या शुल्क की समाप्ति के बाद कीमत प्रभाव की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

31. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

च.1.4 कीमत कटौती

32. पाटित आयातों द्वारा की गई कीमत कटौती की मात्रा का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की है। निवल बिक्री प्राप्ति का आकलन समस्त रिबेटों और करों को घटाने के बाद किया गया है। आयातों के पहुंच मूल्य की गणना 1% हैंडलिंग प्रभार तथा लागू सीमाशुल्क को संबद्ध वस्तु के सीआईएफ मूल्य में जोड़कर की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य के साथ करने पर यहाँ पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान ताइवान तथा यूएई से हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है।

	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
सीआईएफ निर्यात कीमत रु./किग्रा.				
ताइवान	***	***	***	***
यूएई	***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य				
ताइवान	***	***	***	***
यूएई	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति (रु./किग्रा.)	***	***	***	***
बिक्री की लागत (रु./किग्रा.)	***	***	***	***
कीमत कटौती (रु./किग्रा.)				
ताइवान	***	***	***	***
ताइवान - सूचीबद्ध	-100		25.57	51.04
यूएई	कोई निर्यात नहीं	कोई निर्यात नहीं	कोई निर्यात नहीं	***

च.1.5 कम कीमत पर बिक्री

(मूल्य रु./किग्रा.में)

निवल बिक्री प्राप्ति	***
क्षति रहित कीमत	***
पहुंच मूल्य - चीनी ताईपेई	***
कम कीमत पर बिक्री	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	***
कम कीमत पर बिक्री (%) रेंज	35 - 50
पहुंच मूल्य - यूआई	***
कम कीमत पर बिक्री	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	***
कम कीमत पर बिक्री (%) रेंज	70 - 90
पहुंच मूल्य (संबद्ध देश)	***
कम कीमत पर बिक्री	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	***
कम कीमत पर बिक्री रेंज	70 - 90

33. ताइवान एवं यूआई के मामले में कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक रही है ।

च.1.6 कीमत हास/न्यूनीकरण

34. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में हास/न्यूनीकरण हो रहा था, प्राधिकारी ने बिक्री कीमत एवं उत्पादन लागत में प्रवृत्तियों की तुलना की है ।

ईकाई मी.ट. में	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति (रु./मी.ट.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	113	117	126
बिक्री (रु./मी.ट.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	109	107	115

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत में वृद्धि हुई है । तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि से अधिक रही है ।

छ. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

36. नियमों के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन उत्पादों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शुरू होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों के आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों तथा बिक्री, लाभ, उत्पादन बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक तथा संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन, नकद मालसूचियों पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

छ.1 उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग

37. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग निम्नानुसार रहा है :-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
क्षमता	मी.ट.	1669	1669	1790	1790
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	107	107
उत्पादन	मी.ट.	1341	1477	1624	1690
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	121	126
घरेलू बिक्री	मी.ट.	241	279	332	355
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	138	147
क्षमता उपयोग	%	80	89	91	94
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	118

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं बिक्री में समग्र रूप में वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग भी आधार वर्ष के दौरान 80% से बढ़कर जांच अवधि में 94% हो गया है।

छ.2 लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद प्रभाव:

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
लाभ/(हानि) (पीबीटी)	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(13.33)	264.23	319
ब्याज पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	195	342	378
निवेश पर आय (एनएफए आधारित)	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	209	214
नकद लाभ	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	41.84	485	621

39. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष के दौरान *** लाख रुपए का घाटा हुआ था जो वर्ष 2006-07 में घटकर *** लाख रुपए हो गया। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2006-07 तथा जांच अवधि के दौरान लाभ कमाया और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का समग्र लाभ *** लाख रुपए तक रहा है।

40. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक निवेशों पर अपनी आय में सुधार किया है। निवेशों पर आय आधार वर्ष के दौरान ***% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान ***% हो गई।

41. प्राधिकारी ने इन वर्षों के दौरान नकद लाभ की जांच की है और नकद लाभ के बारे में उपलब्ध स्थिति से यह पता चलता है कि इसमें क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। आधार वर्ष के दौरान नकद लाभ *** लाख रुपए अर्थात् नकारात्मक था जो जांच अवधि में *** लाख रुपए के लाभ में तब्दील हो गया।

छ.3 रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	107	119	126	126
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	118	118
मजदूरी	रुपए/लाख	378.24	404.83	424.61	475.17
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	112	126
उत्पादकता	मी.ट./व्यक्ति	12.53	12.41	12.89	13.41
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	103	107

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार एवं कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी में समग्र रूप में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में व्यक्ति उत्पादकता में सुधार हुआ है।

छ.4 मालसूधियां

43. घरेलू उद्योग के पास तैयार उत्पादों के औसत स्टॉक में समग्र रूप में वृद्धि प्रदर्शित होती है।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी.ट.	47	34	49	57
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	104	122

छ.5 वृद्धि

44. समग्र अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, बिक्री, लाभ तथा लगाई गई पूंजी पर आय में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

छ.6 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी एक बहु-उत्पाद कंपनी है और उसे नए निवेश जुटाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।

छ.7 क्षति मार्जिन

46. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) तथा पहुंच मूल्य पर विचार करते हुए क्षति अवधि के लिए क्षति मार्जिन का परिकलन निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया गया है :-

	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
उत्पादक/निर्यातक	अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	%	रेंज (%)
चीनी टाईपेई	***	***	***	***	40 -50
यूआई	***	***	***	***	75 - 95

छ.8 क्षति के बारे में निष्कर्ष:

47. विचाराधीन उत्पाद अलग-अलग रूपों में सन/डस्ट कंट्रोल पालिस्टर फिल्म है। समान वस्तु के लिए क्षति विश्लेषण इसके विभिन्न रूपों के आयातों का प्रभाव समझने के लिए किया गया है और इस मामले में प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हुए हैं :-

- (i) आधार वर्ष अर्थात् 2004-05 की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 80% (सूचीबद्ध) की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने क्षमता में 7% (सूचीबद्ध) और उत्पादन में 26% (सूचीबद्ध) की वृद्धि की है। तथापि, क्षमता वृद्धि के बाद क्षमता उपयोग आधार वर्ष 2004-05 में रहे 80% की तुलना में बढ़कर 94% हो गया है।
- (ii) संबद्ध देशों से इतर देशों का बाजार हिस्सा वर्ष 2004-05 में 10.48% से बढ़कर जांच अवधि में 26.77% हो गया है।

(iii) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2004-05 में 88.65% से घटकर 2004-05 में 72.58% हो गया है ।

(iv) आधार वर्ष को छोड़कर क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा 1% से कम रहा है ।

ज.1 अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

ज.1.1 अन्य स्रोतों से आयातों का मूल्य तथा कीमत

48. समस्त देशों से हुए कुल आयात वर्ष 2004-05 में 30.84 मी.ट. से बढ़कर जांच अवधि में 134.16 मी.ट. हो गए हैं । घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को संबद्ध देशों से इतर देशों में कब्जे में ले लिया है ।

ज.1.2 मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

49. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 80% (सूचीबद्ध) की वृद्धि हुई है । अतः मांग में कमी ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हो सकता है ।

ज.1.3 विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

50. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार विद्यमान नहीं है । अतः यह करक घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाला कारण नहीं हो सकता है ।

ज.1.4 प्रौद्योगिकी विकास तथा निर्यात निष्पादन

51. घरेलू उद्योग के लिए और समग्र देशों के उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी एक समान है और तदनुसार प्रौद्योगिकी विकास ऐसा कोई कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हो सकता है ।

52. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने *** मी.ट. का उत्पाद किया है जो कुल उत्पादन का ***% है । तथापि, जांच अवधि के दौरान निर्यात बिक्री *** रूपए प्रति किग्रा. की घरेलू बिक्री प्राप्ति की तुलना में *** रूपए प्रति किग्रा. रही है और निर्यात बिक्री पर घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता ।

ज.1.5 घरेलू उद्योग की उत्पादकता

53. प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में परिकलित घरेलू उद्योग की उत्पादकता वर्ष 2004-05 में 12.53 मी.ट./व्यक्ति से बढ़कर जांच अवधि में 13.41 मी.ट. हो गई है और इसे घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है।

झ. कारणात्मक संबंध, पाटन तथा क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना:**घरेलू उद्योग के विचार**

54. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

- (i) घरेलू उद्योग के निवेश पर आय अभी भी अपर्याप्त है।
- (ii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पर्याप्त गिरावट आई है और शुल्क लागू न होने वाले अन्य देशों से हुए आयातों में जांच अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि होगी।
- (iii) भारतीय बाजार में पाटित सामग्री की सतत उपलब्धता के कारण जिस कीमत पर घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की बिक्री की जा रही है, उससे घरेलू उद्योग को यथोचित राहत उपलब्ध नहीं होगी।
- (iv) लाभ, निवेश पर आय तथा नकद लाभ जैसे विभिन्न कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में सुधार होने के बाद भी निवेश पर आय पर्याप्त नहीं रही है।
- (v) शुल्क समाप्त किए जाने पर संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा क्षतिरहित कीमत से कम पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का परिवेश होगा।
- (vi) सार्वजनिक सुनवाई में किए गए अनुरोधों के अनुक्रम में अपने लिखित अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तु की वैश्विक क्षमता तथा मांग के बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है। :

उत्पादन का देश	क्षमता (एलएसएफ)	स्थानीय मांग (एलएसएफ)	बेशी मात्रा (एलएसएफ)	क्षमता (मी.ट.)	कुल मांग (मी.ट.)	बेशी मात्रा (मी.ट.)
कोरिया	750	500	250	674	449	225
ताइवान	720	200	520	647	180	467
चीन	5000	4000	1000	4494	3595	899

अमरीका	10000	3000	7000	8988	2696	6292
यूरोप		1900	(1900)	-	1708	(1708)
मध्य पूर्व तथा अफ्रीका	500	800	(300)	449	719	(270)
भारत	2000	547	1453	1798	491	1306
रूस		1500	(1500)	-	1348	(1348)
कुल	18970	12447	6523	17050	11187	5863
भारत को छोड़कर कुल	16970	11900	5070	15253	10696	4557

याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त सूचना के अनुसार विश्व की उत्पादन क्षमता (भारत को छोड़कर) 16, 970 एलएसएफ है, जबकि मांग केवल 11,900 एलएसएफ की है और क्षमताएं मांग के अतिरिक्त लगभग 50% हैं । इसके अलावा, ताइवान की उत्पादन क्षमता 720 एलएसएफ है, जबकि उनकी मांग केवल 200 एलएसएफ है जिससे उनके पास 520 एलएसएफ की बेशी क्षमता बच जाती है । याचिकाकर्ता ने यह भी सूचित किया है कि यूआई संबद्ध वस्तु का उत्पादक देश नहीं है और यह केवल व्यापारिक देश है और वह संबद्ध वस्तु का वैश्विक रूप से उपलब्ध किसी मात्रा का निर्यात नहीं कर सकता है ।

- (vii) याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी निर्यातकों को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है । जब तक निर्यातक इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने, उसमें वृद्धि होने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, तब तक यह माना जाना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी या उसमें वृद्धि होगी।
- (viii) याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि निर्यातक के पास घरेलू मांग के अतिरिक्त पर्याप्त क्षमता है और उसे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद की मांग के बारे में सूचना प्रदान करनी चाहिए ।

55. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध भी किए हैं कि:-

- (i) संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी समस्त कार्टियों को असहोगी मानने की कृपा करें ।
- (ii) निर्यात कीमत की गणना करते समय गौण स्रोतों से प्राप्त सौदेवार आंकड़ों पर भी किसी अभिभावी प्रभाव के बिना डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों के साथ विचार करें ।

- (iii) तीसरे देशों के संबंध में प्रकटन विवरण में विचारित आयातों की मात्रा जांच अवधि के लिए अधिक बताई गई प्रतीत होती है ।
- (iv) ताईवान से हुए आयात शुल्क लागू होने के बावजूद जारी रहे । यद्यपि, मात्रा में कमी आई और इससे यह पता चलता है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत को पाटित कीमतों पर पर्याप्त आयात होंगे ।
- (v) जांच अवधि में यूएई से हुए आयातों की पुनः शुरुआत हुई ।
- (vi) वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसलिए आयातों में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार हेतु एक आवश्यक पूर्व शर्त नहीं है और वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क की अवधि उन स्थितियों में बढ़ाई जा सकती है जब उत्पाद का कोई निर्यात न हुआ हो ।
- (vii) बिक्री कीमत में वृद्धि पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के कारण ही बिक्री लागत में हुई वृद्धि से अधिक रही है । इसी प्रकार पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग ने विभिन्न आर्थिक मापदंडों में सुधार किया है ।
- (viii) वर्तमान स्थिति से स्पष्ट तौर पर यह संकेत मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहेगा और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क एक बार समाप्त किए जाने पर पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होगी तथा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन में आनुपातिक रूप से पर्याप्त और सतत वृद्धि होने की संभावना है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

56. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए समस्त मुद्दों को नोट किया है और उन पर अंतिम जांच परिणामों में उचित स्थानों पर कार्रवाई की है । प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया है कि:-

- (i) उपर्युक्त पैरा 32 में किए गए उल्लेख के अनुसार ताईवान तथा यूएई से हुए पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती की जा रही है ।
- (ii) घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है जैसा कि अलग-अलग आर्थिक मापदंडों से स्पष्ट हो जाता है । तथापि, संबद्ध देशों द्वारा पाटन जारी रखने या उसकी पुनरावृत्ति करने की स्थिति में क्षति हो सकती है ।
- (iii) पाटन मार्जिन का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से प्राप्त वास्तविक निर्यात सौदों और सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर यह नोट किया गया है कि इन सौदों के लिए पर्याप्त पाटन मार्जिन रहा है जिससे यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन जारी है । इससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से

पाटन जारी रहने की संभावना है क्योंकि ऐसा कोई अन्य कारक जानकारी में नहीं आया है जिससे यह पता चल सके कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन बंद हो सकता है ।

- (iv) क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान ताइवाइन एवं यूएई से हुए आयात मामूली रहे हैं और तदनुसार आयातों की इतनी न्यून मात्रा के आधार पर विशिष्ट पाटन मार्जिन न्यायोचित नहीं पाया गया है क्योंकि यह प्रतिनिधिक आयात के आंकड़ों पर आधारित नहीं है । यह स्पष्ट है कि लागू शुल्क संबद्ध देशों से हो रहे पाटन के लिए प्रभावी किया गया है । अतः मौजूदा शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाती है ।
- (v) यद्यपि, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है, तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत में वृद्धि हुई है और वर्ष 2006-07 तथा जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत, बिक्री लागत से अधिक रही है एवं कीमत में कोई ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है । ऐसा संबद्ध देशों से हुए पर्याप्त पाटित आयातों के कारण हुआ है ।
- (vi) संबद्ध वस्तु की कुल वैश्विक उत्पादन क्षमता 10696 मी.ट. की मांग की तुलना में केवल 15253 मी.ट. (भारत को छोड़कर) रही है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु की 4557 मी.ट. की बाजार में बेशी मात्रा बच गई है । उपलब्ध भारी बेशी मात्रा के लिए हमेशा बाजार तलाशने की प्रवृत्ति रही है । यूएई के मामले में जो एक व्यापार केन्द्र है, यह बेशी क्षमता भारत को निर्यात के लिए उपलब्ध है । इसी प्रकार ताइवान की कुल मांग उनकी उत्पादन क्षमता से काफी कम है जिससे पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात हेतु 467 मी.ट. की बेशी बाजार क्षमता उपलब्ध हो गई है ।
- (vii) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति *** रुपए प्रति किग्रा. रही है जबकि इसी अवधि के दौरान ताइवान तथा यूएई से निवल निर्यात कीमत क्रमशः *** रुपए प्रति किग्रा. और *** रुपए प्रति किग्रा. रही है । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति तथा संबद्ध देशों से निवल निर्यात कीमत के बीच भारी अंतर से पाटनरोधी उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की उच्च संभावना है ।
- (viii) संबद्ध देशों से पाटित आयात काफी कम रहे हैं और घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप निवल बिक्री प्राप्ति को बढ़ाने में समर्थ रहा है । शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में निवल निर्यात कीमत में भारी अंतर के कारण संबद्ध देशों से भारी मात्रा में आयात होने की संभावना है ।

- (ix) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना आवश्यक है ताकि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति न हो सके ।

अंतिम जांच परिणाम:

57. हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा किए गए अनुरोधों और हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों के जरिए अथवा उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज अन्य अनुरोधों के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन तथा क्षति की वर्तमान एवं संभावित स्थिति तथा पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- i) संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है तथा ताइवान एवं यूएई से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन पर्याप्त एवं न्यूनतम सीमा से अधिक है ।
- ii) संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश किए जाने की संभावना है और ताइवान एवं यूएई से हुए आयातों के संबंध में संभावित पाटन मार्जिन पर्याप्त तथा न्यूनतम सीमा से अधिक होगा ।
- iii) वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश करने की संभावना है ।
- iv) इसके अलावा, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसमें वृद्धि होने की संभावना है ।

भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

58. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं । तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की पद्धति द्वारा प्राप्त अनुचित

लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का हास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकेंगे।

59. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से होने वाले आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

सिफारिशें

60. इस आशय का निष्कर्ष निकालने के बाद कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में ताईवाइन एवं यूएई से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अतः प्राधिकारी का यह मत है कि इन देशों से हुए आयातों के संबंध में उपाय की अवधि बढ़ाई जानी अपेक्षित है। तथापि, लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और दिनांक 30.7.2004 की अधिसूचना सं. 14/53/2002-डीजीएडी द्वारा संस्तुत एवं 29.9.2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 101/2004-सी.शु. द्वारा संबद्ध देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जिसे 29.8.2008 की सी.शु. अधिसूचना सं. 100/2008-सी.शु. द्वारा 25 अगस्त, 2009 तक बढ़ाया गया है, को जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

61. केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

अह. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2009

Final Findings

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed against import of Sun/Dust Control Polyester Film originating in or exported from Taiwan & UAE.

BACKGROUND

F. No. 15/17/2008-DGAD.— Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty vide Notification No. 14/53/2002-DGAD dated 25.07.2003 and such provisional duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No. 133/2003 dated 26.08.2003. The Authority issued its Final findings recommending imposition of definitive Anti Dumping Duty on imports of **Sun/Dust Control Polyester Film** (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from UAE and Chinese Taipei (Taiwan) (hereinafter referred as subject countries) vide Notification No.14/53/2002-DGAD dated 30.07.2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No. 101/2004 dated 29.9.2004.

2. The Designated Authority, in terms of section 9A (5) of said Act received a substantiated application from M/s. Garware Polyesters Limited, Mumbai requesting for review and continuation of the Anti-Dumping Duties levied on the subject goods, for another five years on the grounds that the imports from the subject countries had continued in spite of imposition of anti-dumping duty. It was also claimed that expiry of measure against the subject countries would likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Designated Authority issued a Public Notice No. 15/17/2008-DGAD dated 14th August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti Dumping Duty (Sunset Review) investigations, to examine whether the expiry of Anti Dumping Duty would lead to continuation or recurrence of dumping, injury or both.

A. PROCEDURE

3. In these proceedings the procedure described below has been followed:

- i) After initiation of the review, the Authority sent questionnaires, along with the initiation notification, to the known exporters/producers in the subject countries in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information.
- ii) The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- iii) Questionnaires were sent to the known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4),
- iv) Copies of the Initiation Notification were also sent to FICCI, CII and ASSOCHAM for wider circulation.
- v) None of the exporters/ producers from subject countries have responded to the Authority with prescribed questionnaire response.
- vi) No other interested party filed any response to the Initiation Notification.
- vii) M/s. Garware Polyesters Limited, Mumbai being domestic industry, submitted the information/data. The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to examine the injury suffered, to work out optimum cost of production, cost to make and sell the subject goods in India and so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- viii) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidential claim. On being satisfied, the Authority granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide Non-Confidential Version of the information filed on confidential basis.
- ix) Transaction-wise data of imports for the period of investigation and preceding three years were called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) in addition to the data of IBIS provided by the domestic industry.

- x) ***in the statement represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xi) The Authority held a public hearing on 17.7.2009 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of interested parties. The written submissions received from interested parties have been considered in this findings;
- xii) Investigations were carried out for the Period of Investigation (POI) from 01.04.2007 to 31.3.2008. However, injury analysis covers the periods 2004 - 05, 2005 - 06, 2006 - 07 and the Period of Investigation.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

4. The product under investigation in the present case is "Specialty Polyester Film i.e. Sun/Dust Control Polyester Film" originating in or exported from Taiwan & UAE and is also known by different names in the trade and market parlance such as Sun Control Films, Sun Films, Solar Films, Solar Control Films, Solar Window Films, Window Films. The Product is largely used for heat rejection/glare reduction, U.V. rejection and safety by applying on window glasses of automobiles as well as buildings etc. Sun/Dust Control Polyester Film is applied to the inner side of the glass windows. Its main function is to reduce the solar heat glare, ultra violet light and glare that normally would enter through the windows. The Sun/Dust Control Polyester Film is classified under Customs Tariff Heading 39 20 69 under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975, and 39.20.69.04 under Indian Custom Tariff Classification. The Classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations. The present investigation is a review investigation and the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. Furthermore, there is no claim of significant development or change in the product during the period thereafter. The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. There is no submission from any exporter/producer or any interested party disputing the product under consideration and like article. The subject goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territories within the meaning of the Rules.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING:

5. In the original investigations, M/s. Garware Polyesters Limited, Mumbai had filed the petition before the Authority. The Sunset Review application has been filed by M/s. Garware Polyesters Limited, Mumbai as the domestic industry. There is no other producer of subject goods in India and the petitioner being the sole producer of the subject goods constitutes domestic industry within the meaning of the Anti Dumping Rules. The investigation has not shown any fact to the contrary to what has been claimed and established by the petitioner. Having regard to the Rules and information on record, the Authority holds that M/s. Garware Polyesters Limited, Mumbai constitute domestic industry for the purpose of the present investigations within the meaning of the Rules.

D. DUMPING MARGIN**D.1 METHODOLOGY OF DETERMINATION**

6. There is no response from any producer/exporter from Taiwan and UAE. The Authority has recorded the Final Findings on the basis of best available information in view of non cooperation from the exporters/producers from the subject countries.

D.2 Examination by the Authority**D.2.1 NORMAL VALUE**

7. No exporter/producer from the subject countries has cooperated in the investigation to enable to determine normal value and export price of the subject goods in their countries and the Authority notes the following:..

- (i) The petitioner has stated that they made efforts to get information on prices at which the subject goods were being sold by the exporters in their domestic markets. However, the price at which the material has been exported to India is far below the costs associated with production of the subject goods.
- (ii) The petitioner has stated that they have exported the product under consideration to Taiwan. The product is not directly consumed in Taiwan. The product is resold by the importers. The price at which the goods exported by the petitioner is resold by the importer in Taiwanese market has to be materially higher than the price at which the petitioner has exported the subject goods. The price at which petitioner has exported the subject goods to Taiwan has been at least lower than the price at which the product under consideration was being sold in the Taiwanese market. The petitioner has argued that the price at which the petitioner has sold the product in Taiwan is a conservative estimate of normal value in Taiwan.
- (iii) That the production process for the product under consideration does not involve substantial production technology or manufacturing process. It also does not appear that scale of operations could make substantial difference in the cost of production. In view of these facts the Authority has worked out the normal value on the basis of constructed value method and has adopted the most conservative method, even if there is no cooperation from any exporter/producer in this case.
- (iv) That the polyester film forms the basic raw material for production of the subject goods. Further, a number of chemicals/compounds are used to make the subject goods.
- (v) The normal value assessed on two alternate basis on comparison shows that normal value based on estimates of cost of production appears to be more conservative and reasonable. Under the circumstances, as explained above, normal value has been worked out on cost of production with reasonable addition for selling, general, administration costs and profit in accordance with Rules 6(8) supra.

Taiwan

8. In the absence of any information from any exporter/producer, the Authority has determined the normal value on the basis of best available information. Normal value for Taiwan has been constructed on the basis of international prices duly adjusted by amount of custom duty on major raw material, ocean freight and marine insurance. Other raw materials, conversion cost, general and administrative and selling expenses have been adopted as per domestic industry's cost of production together with a 5% margin of profit. The Normal Value of the subject goods has been determined as Rs *** (US\$ ***) per Kg at the exchange Rate of Rs40.75=US\$1.00

UAE

9. In the absence of any information from any exporter/producer, the Authority has determined the normal value on the basis of best available information. Normal value for UAE has been constructed on the basis of international prices duly adjusted by amount of custom duty on major raw material, ocean freight and marine insurance. Other raw materials, conversion cost, general and administrative and selling expenses have been adopted as per domestic industry's cost of production together with a 5% margin of profit (excluding interest). The Normal Value of the subject goods has been determined as Rs *** (US\$ ***) per Kg at the exchange Rate of Rs40.75=US\$1.00

D.2.2 EXPORT PRICE

10. The Petitioner has provided information on imports on the basis of actual imports data provided by the secondary agency, M/s. Informant, Mumbai. The transaction wise data was called from DGCI&S for the POI and previous three years and same was received. From the data it has been observed that different products have been imported under the particular classification. However, data of the subject goods from subject countries has been examined and it has been observed that there was only one transaction from each of the subject country, reflecting meager quantity of import. In the absence of actual export price from the exporters, the Authority has adopted this information for assessment of the export price from the countries involved.

11. The Authority has worked out the weighted average export price after adjustments towards ocean freight and insurance in view of complete non cooperation by the concerned exporters.

Taiwan

12. CIF Export Price of imports from Taiwan has been arrived at Rs ***/Per Kg i.e. US\$ ***/Per Kg and after adjustments towards ocean freight and insurance, net export price has been determined as Rs. *** (US\$ ***) Per Kg.

UAE

13. , CIF Export Price of imports from UAE has been arrived at Rs ***/Per Kg i.e. US\$ ***/Per Kg. and after adjustments towards ocean freight and insurance, net export price has been determined as Rs. *** (US\$ ***) Per Kg.

D.3 DUMPING MARGINS

14. The rules relating to comparison of export price to the normal value of the subject goods in the country of exports provides as follows:-

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sales, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability"

15. In terms of the above Rules the authority carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average net export price for evaluation of dumping margin.

16. In view of the lack of cooperation, the normal value of the subject goods from both the subject countries have been constructed on the basis of best available information and the weighted average normal value has been adopted for the purpose of determination of dumping margin. The weighted average net export price has also been estimated on the basis of DGCI&S import data with admissible adjustments as stated earlier. The Authority thus considers that the comparison of normal value with the export price is fair within the meaning of Annexure I to the Rules.

17. Accordingly, the dumping margins for the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have been worked out as under:-

Country-wise Exporters/Producers	Normal Value US\$/perKg.	Export Price US\$/perKg.	Dumping Margin US\$/per Kg.	Dumping Margin (%)
Taiwan All exporters	***	***	***	***
UAE All exporters	***	***	***	***

18. The Authority notes that the dumping margin determined in the previous investigation was quite significant. The present investigation also shows significant dumping margin from the subject countries.

E. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

E.1 INJURY AND CAUSAL LINK

E.1.1 Views of the Petitioner

19. The petitioner has submitted as under : -

- (i) Even after the improvement in the performance of the domestic industry, return on investment is still insufficient.
- (ii) The subject goods would enter the Indian market from subject countries at dumped prices below the selling price and non-injurious price of the domestic industry.
- (iii) That the subject countries have huge freely disposable/unutilized/surplus capacities for export to India and injury to the domestic industry is likely in the event of revocation of anti dumping duties.
- (iv) *In a situation where the dumping continues or is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duty and where the domestic industry continues to be injured or the injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duty, the anti dumping duty in force should be continued further for a period of five years. In the instant case, dumping of the product from the subject countries has continued. Dumping would intensify, should the present anti dumping duty be revoked.*
- (v) *However, if Authority finds that the domestic industry has not suffered continued injury, petitioner then claims that the revocation of duties would be likely to lead to recurrence of injury due to imports from Taiwan and UAE. As regards injury, all parameters collectively and cumulatively show that the performance of the domestic industry improved after imposition of anti dumping duty against subject countries and consequent restriction on dumping and injury to the domestic industry is likely in case of revocation of duty.*

E.1.2 Views of the exporters, importers, users & other interested parties

20. There has been no response from any exporter/producer from the subject countries, importers and other interested parties. At the time of Public Hearing following submissions have been made on behalf of UAE Government:-

- (i) There are low volumes of imports from UAE.
- (ii) The imports from UAE are just 4% of total imports in the entire injury period and 1% of total imports in the POI. It is just 11% of the imports from Taiwan. There should be no cumulative assessment for Taiwan and UAE.

- (iii) In non-confidential version of the petition, petitioner confirms that there are no imports from UAE.
- (iv) Sufficient evidence is required to prove recurrence of injury and the requirement of "positive evidence and objective examination" is to be satisfied under Art. 3.1.

E.1.3 Examination by the Authority

21. The Authority has taken note that for the sunset review, the relevant provisions of Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act read as under:

"The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension."

22. The Authority further notes that:

- (i) Rule 23 of the Anti-dumping Rules provide for procedure for conducting sunset review. For conducting the review, the provisions of Rule 6, 7,8,9/10, 11, 16,17,18,19 and 20 have been made applicable.
- (ii) In this regard Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- (iii) For the purpose of assessing present state of injury, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

23. The Authority considered the following for examining the issue of cumulative assessment of injury and observed that:

- (i) The domestic product and product supplied by producers in subject countries are like articles.
- (ii) Imported products and domestically produced subject goods are interchangeable and are being interchangeably used. Transaction-wise information on imports from various countries shows that the imports are primarily being made by traders who have purchased the material for reselling. Goods supplied by the two countries were, therefore, competing in the same market.
- (vi) Products supplied from the subject countries have been marketed in India during the same period through comparable sales channels and under similar commercial conditions.
- (vii) The domestic producer and exporters in the subject countries have been selling the product to the same category of consumers.

24. The Authority holds that cumulative assessment of injury is appropriate in this case since the exports from the subject countries were directly competing amongst themselves as well as with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market.

F. Injury Determination

F.1 Assessment of demand

25. For the calculation of the domestic consumption/demand of the product under consideration, the Authority has considered the sales volume of the domestic industry as well as the total imports into India.

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Domestic Sales of Domestic industry	MT	241	279	332	355
Trend	MT	100	116	138	147
Imports from subject countries	MT	2.36*	0	0.444	3.198
Trend		100	0	19	136
Imports from other Countries	MT	28.48	80.63	131.86	130.96
Trend		100	283	463	460
Total Imports	MT	30.84	80.63	132.30	134.16
Trend		100	261	429	435
Demand	MT	271.84	359.63	464.30	489.16
Trend		100	132	171	180
Export Sales of Domestic industry	MT	1136	1189	1276	1288
Trend		100	105	112	113

26. The Authority notes that the demand has shown a positive trend over the injury period and increased by 80% in POI from the base year 2004-05, while domestic sales have increased by 47% during the same period. The imports from the subject countries have been meager throughout the injury period.

F.1.2 Import volumes and market share

27. With regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under: -

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India"

28. The Authority has examined the claim of the domestic industry as per DGCI&S data. The Authority has determined the volume of imports based on DGCI&S source only.

Particulars	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Market share in Imports					
Taiwan	MT	2.36	-	0.444	1.076
Trend	Indexed	100	0	19	45.59
UAE	MT	-	-	-	2.122
Trend	Indexed	-	-	-	-
Subject Countries	MT	2.360	-	0.444	3.198
Trend	Indexed	100	-	19	136
Other Countries	MT	28.48	80.63	131.86	130.96
Trend	Indexed	100	283	463	460
Total Imports	MT	30.84	80.63	132.30	134.16
Trend	Indexed	100	261	429	435
Sales of Domestic Industry	MT	241	279	332	355
Trend	Indexed	100	116	138	147
Total Demand		271.84	359.63	464.30	489.16
Trend	Indexed	100	132	171	180
Market share in Imports					
Taiwan	%	7.65	-	0.34	0.80
UAE	%	-	-	-	1.58
Subject Countries	%	7.65	-	0.34	2.38
Other Countries	%	92.35	100	99.66	97.62
Market share in Demand					

Chinese Taipei	%	0.87	-	0.11	0.22
UAE	%	-	-	-	0.43
Subject Countries	%	0.87	-	0.11	0.65
Other Countries	%	10.48	22.48	28.39	26.77
Domestic industry	%	88.65	77.58	71.50	72.58

29. The Authority notes that:

- (i) The share of subject countries in total imports into India declined from 7.65% in the base year 2004-05 to "Nil" in 2005-06 and thereafter increased to 0.34% in 2006-07 and 2.38% during POI. Except base year and POI, share of subject countries in the total imports remained even less than one percent.
- (ii) The market share in demand in respect of imports from the subject countries was only 0.87% during base year and further reduced to the level of 0.65% during POI. The share of subject countries in total demand is only 0.65% during POI which is meager and negligible. At the same time, share of other countries have increased from 10.48% to 26.77% over the same period. The share of domestic industry, which was 88.65% during 2004-05 has declined to 72.58% during POI.

F.1.3 Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry

30. In a review investigation, it is required to examine whether there has been a significant price effect by the dumped imports as compared with the price of like product in India or whether there is likelihood of recurrence of price effect after revocation of duty.

31. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

F.1.4 Price undercutting

32. In order to ascertain the price undercutting being caused by the dumped imports, the Authority has compared net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports. The net sales realization has been arrived after deducting all rebates and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charges and applicable basic customs duty to the CIF value of subject imports. The landed value of imports compared with net sales realization of the domestic industry shows that the imports from Taiwan and UAE have been undercutting the prices of the domestic industry during POI.

	2004-05	2005-06	2006-07	POI
CIF export price Rs/Kgs				
Taiwan	***	***	***	***
UAE	***	***	***	***
Landed price of imports				

Taiwan	***	***	***	***
UAE	***	***	***	***
Net sales realization (Rs/Kgs)	***	***	***	***
Cost of sales (Rs/kgs.)	***	***	***	***
Price undercutting price Rs/Kgs				
Taiwan	***	***	***	***
Taiwan - Indexed	-100	-	25.57	51.04
UAE	No export	No export	No export	***

F.1.5 Price Underselling

	(Value in Rs./Kgs)
Net Sales Realisation	***
Non Injurious Price	***
Landed Value - Chinese Taipei	***
Price Underselling	***
Price Underselling (%)	***
Price Underselling (%) range	35 – 50
Landed value - UAE	***
Price Underselling	***
Price Underselling (%)	***
Price Underselling(%) range	70 – 90
Landed value (Subject Countries)	***
Price Underselling	***
Price Underselling (%)	***
Price Underselling range	70 – 90

33. The price underselling have been positive in case of Taiwan and UAE.

F.1.6 Price suppression/depression

34. In order to assess whether the imports from the subject countries were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry, the Authority compared the trends in selling prices and cost of production.

Unit in Kg..	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Net sales realization (Rs/Kg)	***	***	***	***
Trend	100	113	117	126
Cost of sales (Rs/Kg.)	***	***	***	***
Trend	100	109	107	115

35. The Authority notes that selling prices and cost of sales of the domestic industry increased over the years, however, increase in selling price is higher than the increase in cost of sales.

G. Economic Parameters relating to the Domestic Industry

36. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic

producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

G.1 Production, sales, capacity and capacity utilization

37. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry has been as under:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Capacity	MT	1669	1669	1790	1790
Trend	Indexed	100	100	107	107
Production	MT	1341	1477	1624	1690
Trend	Indexed	100	110	121	126
Domestic sales	MT	241	279	332	355
Trend	Indexed	100	116	138	147
Capacity utilization	%	80	89	91	94
Trend	Indexed	100	111	114	118

38. The Authority notes that capacity, production and sales of the domestic industry have increased in absolute terms. Capacity utilisation also increased from 80% during base year to 94% during the POI.

G.2 Profit, return on capital employed and cash flow:

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Profit/(Loss) (PBT)	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(13.33)	264.23	319
Profit/(Loss) before interest (PBIT)	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	195	342	378
Return on investment (NFA basis)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	156	209	214
Cash profits	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	41.84	485	621

39. The loss to the domestic industry to the tune of Rs *** lakh during base year reduced to Rs ***lakh during 2005-06. The domestic industry made profit during 2006-07 and POI and absolute profit to the domestic industry during POI has been to the tune of Rs. ***lakh.

40. The domestic industry improved its return on investments from base year to POI. Return on investment improved to ***% during POI from ***% during the base year.

41. The Authority has examined cash profits over the years and the position with regard to cash profit shows that it has been continuously improving over the injury period and POI. Cash profit during the base year was Rs. (***) lakh i.e. negative and converted to profit to the tune of Rs. ***lakh during POI.

G.3 Employment, wages and productivity

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Number of employees	Nos.	107	119	126	126
Trend	Indexed	100	111	118	118
Wages	Rs./Lacs	378.24	404.83	424.61	475.17
Trend	Indexed	100	107	112	126
Productivity	MT/person	12.53	12.41	12.89	13.41
Trend	Indexed	100	99	103	107

42. The Authority notes that employment and wages to employees has improved in absolute term. Productivity, expressed in terms of production per employee shows improvement.

G.4 Inventories

43. Average stock of finished products with the domestic industry shows increasing trend in absolute term.

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Average stock	Mt	47	34	49	57
Trend	Indexed	100	72	104	122

G.5 Growth

44. The capacity, production, capacity utilisation, productivity, sales, profits and return on capital employed have shown positive growth throughout the period.

G.6 Ability to raise capital investments

45. The Authority notes that the petitioner company is a multi-product company and may not have difficulty in raising fresh investment.

G.7 Injury margin

46. Considering the Non-injurious price (NIP) and landed value, injury margin has been arrived for the investigation period as given in the following table.

	NIP	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
Producer/Exporter	US\$/MT	US\$/DMT	US\$/DMT	%	Range (%)

Taiwan	***	***	***	***	40 – 50
UAE	***	***	***	***	75 – 95

G.8 Conclusion on Injury:

47. The product under consideration is Sun/Dust Control Polyester Film in its different forms. The injury analysis for like article has been analyzed to understand the impact of the imports of its various forms and following facts are before the Authority in this case:-

- (i) The demand of subject goods has increased by 80% (indexed) during POI as compared to base year i.e. 2004-05. During this period, the domestic industry has increased capacity by 7% (indexed) and production by 26% (indexed). The capacity utilization, after enhancement in capacity has however, increased to 94% during POI in comparison to 80% from the base year 2004-05.
- (ii) The market share of countries other than subject countries has increased from 10.48% in 2004-05 to 26.77% during POI.
- (iii) The market share of the domestic industry has declined from 88.65% during 2004-05 to 72.58% during POI.
- (iv) The market share of dumped imports from subject countries has remained even less than one percent during injury period and POI except in the base year.

H.1 Others Known Factors and Causal Link:

H.1.1 Volume and prices of imports from other sources

48. The total Imports from all countries increased from 30.84 MT in 2004-05 to 134.16 MT in POI. The declined market share of domestic industry has been captured by countries other than subject countries.

H.1.2 Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

49. The demand of the subject goods has increased by 80% (indexed) during POI as compared to base year. Contraction in demand, therefore, is not a possible reason, which could be affecting the performance of the domestic industry.

H.1.3 Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

50. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. Therefore, this factor could not be reason affecting the performance of the domestic industry.

H.1.4 Development of technology and export performance

51. Technology for production of the product is same for the domestic industry and as used by the producers in the subject countries and accordingly development in technology is not a factor which could affect the performance of the domestic industry.

52. The domestic industry has made exports to the tune of 1288 MT during POI which is ***% of the total production. However, export sales are at Rs. *** per Kg. against domestic sales realization of Rs. *** per Kg. during POI and the export sales cannot be considered a factor affecting the performance of the domestic industry.

H.1.5 Productivity of the Domestic Industry

53. Productivity of the domestic industry measured as production per employee have improved from 12.53 MT/person in 2004-05 to 13.41 MT/person during POI and cannot be considered a factor affecting the performance of the domestic industry.

I. Causal Link, Likelihood of Continuance or Recurrence of Dumping and Injury:

Views of the Domestic Industry

54. The domestic industry has made the following arguments:

- (i) The return on investment of the domestic industry is still insufficient.
- (ii) The market share of the domestic industry has significantly decreased and imports from other countries not attracting duties have increased with the significant surge during the investigation period. The dumped imports from subject countries shall surge in case duties are withdrawn.
- (iii) Due to continued availability of dumped material in the Indian market, the price at which subject goods are being sold by the domestic industry do not provide due relief to the domestic industry.
- (iv) Even after improvement in the performance of the domestic industry in terms of various price parameters, such as profits, return on investments and cash flow has declined from base year and return on investment is not sufficient.
- (v) The subject goods would enter the Indian market from subject countries at dumped prices below the selling price and non-injurious price of the domestic industry on revocation of duties..
- (vi) The Petitioner in their written submissions, in continuation to submissions made in Public Hearing has provided following information on global capacity and demand of the subject goods:

Country of Production	Capacity (LSF)	Local Demand (LSF)	Surplus (LSF)	Capacity (MT)	Local Demand (MT)	Surplus (MT)
Korea	750	500	250	674	449	225
Taiwan	720	200	520	647	180	467
China	5000	4000	1000	4494	3595	899
USA	10000	3000	7000	8988	2696	6292
Europe		1900	(1900)	-	1708	(1708)
Middle East & Africa	500	800	(300)	449	719	(270)
India	2000	547	1453	1798	491	1306
Russia		1500	(1500)	-	1348	(1348)
Total	18970	12447	6523	17050	11187	5863
Total excluding India	16970	11900	5070	15253	10696	4557

As per above information provided by the Petitioner, the production capacity of the World (excluding India) is 16,970 LSF whereas the demand is only 11,900 LSF and the capacities are almost 50% in excess of demand. Further the production capacity of Taiwan is 720 LSF whereas their local demand is only 200LSF resulting into surplus capacity of 520 LSF. The petitioner has also informed that UAE is not a producer country of the subject goods and is only a trading country and can export the subject goods to any extent available globally.

- (vii) The Petitioner has contended that the responding exporters must establish that dumping is unlikely to continue or recur in the event of revocation of anti dumping duties. Unless the exporters establish that dumping is unlikely to continue, intensify or recur in the event of revocation of anti dumping duties, it must be held that the dumping would continue or recur or intensify in the event of revocation of anti dumping duties.
- (viii) The Petitioner has contended that the exporter has significant capacity in excess of domestic demand and must provide information regarding the demand of the product under consideration in subject countries.

55. The domestic industry has also made following submissions on the disclosure statement:

- (i) That none of the producers/exporters of the subject countries have responded to the Authority, the Authority may kindly treat all the parties as non co-operative.
- (ii) That while calculating export price transaction wise data received from secondary sources may also be considered along with the data received from DGCI&S without overlapping.
- (iii) That volume of imports considered in the Disclosure Statement in respect of third countries appears to be overstated for POI.

- (iv) That the imports from Taiwan continued in spite of imposition of duty, though the volumes declined and it shows that there would be significant imports at dumped prices to India in case of revocation of duty.
- (v) That the imports from UAE have re-commenced in the POI.
- (vi) That the present investigation is a Sunset Review investigation and therefore increases in imports is not a necessary pre-condition for extension of anti dumping duties and in fact anti dumping duties can be extended in those situations where there are no exports of the product.
- (vii) That the increase in selling price is higher than the increase in cost of sales only due to anti dumping duties on dumped imports. Similarly, due to anti dumping duties, the domestic industry has achieved improvement in various economic parameters.
- (viii) That the present situation is clearly suggestive that the dumping would continue in the event of revocation of anti dumping duty and volume of dumped imports would increase once the present anti dumping duties are revoked and dumping is likely to continue insignificantly increased proportion in the event of revocation of anti dumping duties.

Examination by the Authority:

56. The present investigation is a sunset review and the Authority is required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority has taken note of all the issues raised by the domestic industry and other interested parties on disclosure statement and have dealt with at appropriate places in the final findings. The Authority has noted as under:

- (i) That dumped imports from Taiwan and UAE have been undercutting the price of the domestic industry as detailed at Para 32 above.
- (ii) The state of domestic industry has improved as evident from different economic parameters. However, in case of continuance or recurrence of dumping by the subject countries, the injury may recur.
- (iii) The dumping margin has been determined on the basis of actual export transactions captured from the DGCIS data and the normal value determined on the basis of best facts available. On the basis of these facts it has been noted that there is significant dumping margin for these transactions indicating that dumping is continuing despite the imposition of anti dumping duty. This indicates that there is likelihood of continuation of dumping from the subject countries as no other factor has come to the notice indicating that the dumping may discontinue in case of revocation of anti dumping duty.
- (iv) That the imports from Taiwan and UAE during injury period & POI were meager and accordingly, specific dumping margin calculated based on such miniscule quantity of imports has not found to be justified, as the same is not based on representative import data. It is evident that the

duty in place has been effective to stall dumping from subject countries. Therefore, continuation of the existing duty is recommended.

- (v) That although there is price undercutting and price underselling, the Authority notes that the selling prices and cost of sales of the domestic industry increased over the years and selling prices have been higher than cost of sales during 2006-07 and POI and there have not been price suppression/depression. This is due to insignificant dumped imports from subject countries.
- (vi) That the total global production capacity (excluding India) has been 15253 MT of the subject goods as against demand of 10086 MT only resulting into market surplus to the tune of 4557 MT of the subject goods. The huge surplus quantity available always have tendency to explore markets. In case of UAE, a trading hub, this surplus capacity is available for export to India. Similarly, the total demand of Taiwan is far less than their production capacity leading to market surplus to the tune of 457 MT available for exports to India at dumped prices.
- (vii) That the net sales realisation of the domestic industry during POI has been Rs. ***/- per Kg. while the net export price from Taiwan and UAE have been Rs. *** per Kg. and Rs. *** per Kg. respectively during the same period. The significant difference between net sales realisation of the domestic industry and net export price from subject countries leads to strong possibility of dumping if anti dumping measures are withdrawn.
- (viii) That the dumped imports from the subject countries have been quite low and domestic industry has been able to increase the net sales realisation on line with the increase in cost of sales. In a situation if duties are withdrawn, there is every likelihood of surge in dumped imports from subject countries due to significant difference in net export price in comparison to net sales realisation of the domestic industry.
- (ix) That taking into consideration the fact and circumstances of the case, it is necessary to continue the anti-dumping duty for further period of five years so that there is no injury to domestic industry due to continuance or recurrence of dumped imports from subject countries.

FINAL FINDINGS:

57. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i) The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from Taiwan and UAE are substantial and above de-minimis.

- ii) The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices and the likely dumping margins in respect of imports from Taiwan and UAE will be substantial and above de-minimis.
- iii) The subject goods are likely to enter Indian market at dumped prices, should the present measures be withdrawn.
- iv) Further, should the present anti dumping duties be revoked, injury to the domestic industry is likely to continue and intensify.

Indian industry's interest and other issues

58. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practice, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

59. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

Recommendations

60. Having concluded that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of imports from Taiwan and UAE, if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended in respect of imports from these countries, however the quantum of anti dumping duty in force need not be revised. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends continuation of Anti Dumping Duty on imports of subject goods from the subject countries recommended vide Notification No. 14/53/2002-DGAD dated 30/7/2004 and imposed vide Customs Notification No. 101/2004-Customs dated 29.9.2004 and further extended upto 25th August, 2009 vide Customs Notification No. 100/2008-Customs dated 29.8.2008.

61. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority